EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

A recent directive from the Ministry of Information and Broadcasting said all satellite TV channels in India are required to obtain authorization from the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) before utilizing foreign satellite services for broadcasting. The direct-to-home (DTH) and teleport companies in India are optimistic that the new policy introduced by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) will lead to a reduction in satellite costs.

The Foreign Direct Investment (FDI) figure saw a quantum increase by 87% in broadcasting and stood at Rs 7012 crore in the March end 2024 as compared to Rs 3754 crore in the previous year.India needs to see a far greater investments in this sector to spur growth.

Several leading broadcasters have initiated discussions with Prasar Bharati to address concerns about ensuring a level playing field in the competitive broadcasting landscape. This move comes as the industry adapts to new regulations and seeks to maintain fairness and competitiveness across all broadcasting platforms.

The proactive engagement between broadcasters and Prasar Bharati marks a crucial step towards addressing regulatory disparities and fostering a fair competitive landscape in India's broadcasting industry. As the discussions progress, stakeholders are optimistic that collaborative efforts will lead to a more balanced and robust broadcasting ecosystem, benefiting both service providers and consumers.

The approval of the Rs 2000 crore fundraising by ZEEL's shareholders marks a significant milestone for the company, setting the stage for future growth and expansion. As ZEEL navigates the evolving media landscape, this strategic move is expected to bolster its market presence and drive sustained success in the competitive entertainment industry. At the same time Reliance Industries Ltd and The Walt Disney Company merger is expected to be completed by October 2024. NCLT has kept the merger scheme for final disposal.

Scat India Trade show 2024 will open from October 17 -19, 2024 at the Jio World Convention Centre. That's where the action will be. Be there to witness and see how the media technology landscape unfolds.

(Manoj Kumar Madhavan)

सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) के एक हालिया निर्देश में कहा गया है कि भारत में सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को प्रसारण के लिए विदेशी सैटेलाइट सवाओं का उपयोग करने से पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। भारत में डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) और टेलीपोर्ट कंपनियां आशावादी हैं कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) द्वारा पेश की गयी नयी नीति से सैटेलाइट लागत में कमी आयेगी।

*प्रसारण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़े में **87%** की वृद्धि देखी गयी है और यह पिछले वर्ष **3754** करोड़ रुपये की तुलना में **2024** के अंत में **7012** करोड़ रुपये हो गया। भारत को विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कहीं अधिक निवेश की आवश्यकता है। कई प्रमुख प्रसारकों ने प्रतिस्पर्धी प्रसारण परिदृश्य में समान अवसर सुनिश्चित करने के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए प्रसार भारती के साथ चर्चा शुरू कर दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उद्योग नये नियमों के अनुकूल हो रहा है और सभी, प्रसारण प्लेटफॉर्मों पर निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखना चाहता है।*

प्रसारकों और प्रसार भारती के बीच सक्रिय भागीदारी नियामक असमानताओं को दूर करने और भारत के प्रसारण उद्योग में एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ रही है, हितधारकों को उम्मीद है कि सहयोगात्मक प्रयासों में से एक अधिक संतुलित और मजबूत प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, जिससे सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

*जेडईईएल के शेयरधारकों द्वारा **2000** करोड़ रुपये के फंड जुटाने की मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भविष्य के विकास और विस्तार के लिए मंच तैयार करता है। जैसे जैसे जेडईईएल विकसित हो रहे मीडिया परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, इस रणनीतिक कदम से इसकी बाजार उपस्थिति को बढ़ावा मिलने और प्रतिस्पर्धी मनोरंजन उद्योग में निरंतर सफलता मिलने की उम्मीद है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दॅ वॉल्ट डिज्नी कंपनी का विलय अक्टूबर **2024** तक पूरा होने की उम्मीद है। एनसीएलटी ने विलय योजना को अंतिम निपटान के लिए रखा है।*

*स्कैट इंडिया ट्रैडशो **2024, 17-19** अक्टूबर, **2024** को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। आपको सारी गतिविधियां यहां देखने को मिलेगी। कृपया वहां उपस्थित रहें और देखें कि मीडिया परिदृश्य कैसे सामने आता है।*

(Manoj Kumar Madhavan)